

प्रधक.

पी०के०महान्ति
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे.

जिलाधिकारी।

चम्पावत।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग देहनाडून दिनांक ३। दिसम्बर, २००७

विषय— पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के अन्तर्गत जनपद चम्पावत हेतु अग्रिम केन्द्रीय सहायता के रूप में धनराशि अवमुक्त करने संबंधी।

महोदय

उपर्युक्त विषयक पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या N-11019/504/2007-POL-I दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के अनुकम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) हेतु भारत सरकार द्वारा जनपद चम्पावत के लिये अवमुक्त की गयी धनराशि ₹० 10.00 लाख (₹० दस लाख मात्र) को राज्यपाल महोदय आपके निर्दर्शन पर रखने की सही स्वीकृति निम्न प्रतिवर्ण्यों के अधीन प्रदान करते हैं—

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि का उपयोग पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) की ग्यारही पंचवर्षीय योजना एवं दर्शक जिला योजना 2008-09 की तैयारियों हेतु व्यय किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग जनपद चम्पावत की योजना हेतु किया जाय, किसी अन्य परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।
4. उक्त आवंटित धनराशि को ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सकाम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मार्ग निर्देशक सिद्धान्त के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, योजना आयोग भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार महालंखाकार उत्तराखण्ड प्रभासन का उपलब्ध कराते हुए निर्देशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
6. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करते हुए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तापूरितका, स्टोर पर्चेज रूल्स, टेंडर/कोटेशन एवं मित्राचार्यिता के विषय में शासन द्वारा निर्गत तद दिशालक आदेशों का कड़ाइ से अनुपालन किया जायेगा।
7. व्यय उन्ही मदों/योजनाओं के लिये किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
8. काय की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

9. उक्त स्वीकृत घनतारी चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आवश्यक में अनुदान संख्या-07 के अधीन लेखाशीर्षक-3451-संचिवालय आधिक सेवाये-092-अन्य कार्यालय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये-0102-राष्ट्रीय राम विकास योजना (आरएसए०वै०वाई०)-२०-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे ढाला जायेगा।
10. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासी पत्र संख्या ११९(प्र०) XXVII-4 दिनांक २८-१२-२००७में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी०क०महान्ति)
संघिव।

संख्या ८३/२/ XII /०७ /८२(१०) /२००७ तददिनांक।

प्रतीलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, जोवराय मोटर्स विलिंग, सहारनपुर, रोड, देहरादून।
2. निदेशक, पंचायतीराज मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. उप सलाहकार, योजना आयोग (एम एल पी, प्रभाग), भारत सरकार योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. संघिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी वस्त्रावत।
8. निजी संघिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को ८० मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
9. श्री एल०ए० पन्त, अपर संघिव, वित्त, बजट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, लक्ष्मी रोड, देहरादून/वित्त-१/गार्ड फाईल।
11. विभागीय पत्रावली/ समन्वयक, एन०आई०सी०, संचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

ओआ स
७४ अ०।५८
(आरएपी०फुलोरिया)
सयुक्त संघिव।